खण्ड-08 सत्र-02 अंक-07

मंगलवार 25 मार्च, 2025 04 चैत्र, 1947 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08, सत्र-2 में अंक 06 से 12 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-2 मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04 चैत्र, 1947 (शक) अंक-07

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	वार्षिक बजट 2025-26 का प्रस्तुतिकरण	4-76
2.	अनुपूरक अनुदान मांगें (2024-25) प्रस्तुतिकरण एवं पारण	77-82
3.	विनियोजन (संख्या-1) विधेयक, 2025 का प्रस्तुतिकरण एवं पारण	83-84

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04 चैत्र, 1947 (शक) अंक-07

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अहिर दीपक चौधरी
2. श्री अजय महावर
3. श्री अनिल कुमार शर्मा
4. श्री अशोक गोयल
5. श्री चन्दन कुमार चौधरी
6. श्री गजेन्द्र दराल
7. श्री हरीश खुराना
8. श्री कैलाश गंगवाल
9. श्री करनैल सिंह
10. श्री करतार सिंह तंवर
11. श्री कुलदीप सोलंकी
12. श्री कुलवन्त राणा
13. श्री मनोज कुमार शौकीन
14. श्रीमती नीलम पहलवान
15. श्री नीरज बैसोया
16. श्री ओम प्रकाश शर्मा
17. श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
18. श्री पवन शर्मा
19. श्रीमती पूनम शर्मा
20. श्री राज करन खत्री
21. श्री राजकुमार भाटिया
22. श्री रवि कान्त

23. श्री रविन्दर सिंह नेगी
24. श्री संदीप सहरावत
25. श्री संजय गोयल
26. सुश्री शिखा राय
27. श्री श्याम शर्मा
28. श्री सूर्य प्रकाश खत्री
29. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
30. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान
31. श्री विशेष रवि
32. श्री अनिल झा
33. चौधरी जुबैर अहमद
34. श्री अजय दत्त
35. श्री गजेन्द्र सिंह यादव
36. श्री इमरान हुसैन
37. श्री जितेन्द्र महाजन
38. श्री कुलदीप कुमार
39. श्री मुकेश कुमार अहलावत
40. श्री प्रवेश रत्न
41. श्री पुनरदीप सिंह साहनी
42. श्री सही राम
43. श्री संजीव झा
44. श्री सोम दत्त
45. श्री सुरेन्द्र कुमार
46. श्री तिलक राम गुप्ता
47. श्री उमंग बजाज

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2	मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04 चैत्र, 1947 (शक)	अंक-07

सदन पूर्वाह्न 11.08 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए ।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी सदन की उपराज्यपाल दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनन्दन करता हूं। आज हमारे विधायक माननीय विधायक इस सदन के सदस्य जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं (श्री अनिल कुमार शर्मा) आज उनका जन्म दिन है, इस अवसर पर उनको बहुत-बहुत शुभकामनायें और बधाई। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री डॉ. नरेन्द्र नाथ जी भी एलजी गैलेरी में उपस्थित हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी भी आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण - अब माननीया मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी।

वार्षिक बजट 2025-26

माननीया मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में वित्तिय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं।[1] आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कोई साधारण बजट नहीं है ये। दिल्ली की जनता और पूरा देश आज इस सदन के माध्यम से यह बजट सुन रहा है कि दिल्ली की सरकार नई सरकार जो कि ऐतिहासिक जनादेश ले करके यहां चुनकर आई है। जिनको बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ दिल्ली की जनता ने वोट दिया और यहां भेजा उस सरकार का पहला बजट कैसा होगा, आज यहां पर पूरा देश देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये बजट सिर्फ सरकारी खर्चे और आमदनी का लेखाजोखा नहीं है बल्कि पिछले दस सालों की बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने, ऐसी दिल्ली का बजट आज यहां प्रस्तुत किया जायेगा। मैं और मेरी सरकार दिल्ली वासियों को तथा माँ यमुना को नमन करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इसे समुचित निभाने का संकल्प करती है। हमारा यह बजट बाबा साहेब के समता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योद्य, महात्मा गांधी के सर्वोदय और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सब का साथ, सबका

---

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23381 पर उपलब्ध।

विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन सिद्धान्तों पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यन्त दुख होता है कि पिछले दस सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली फिसलती गई। लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थय सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी, उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कोओपरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला डूसिब पूरी तरह ठप्प। गंदा पानी, बहता सीवर ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी और ऐसे में इस सरकार का हमारे पास आना और इसको चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है सर, किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिर भी मैं इन दो लाईनों के माध्यम से सरकार की मंशा आपको बताना चाहती हूं-

''कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है,
यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है,
हवा की ओट लेकर भी दीया जलता है।''

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज में, आज

तक की सरकारों के राज में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था वो था 78 हजार आठ सौ करोड़ रूपये, कागजों में था हुआ कुछ नही था, कागजों पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 28 सौ करोड़ रूपये घट करके मात्र 76 हजार करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी। घट करके 76 हजार करोड़, परन्तु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है एक लाख करोड़ रूपये का प्रस्तावित किया गया है। एक लाख करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया। एक लाख करोड़ रूपये का बजट। जो कि ना केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला जो कि 31.5 प्रतिशत अधिक है पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, जहां साल दर साल बजट बढने की बजाय घटा, जहां जीडीपी की दर पूरे देश की तुलना में कम रही। राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की गति, आय की जो गति पूरे देश में है उससे कम गति से बढ़ी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार में ना तो क्षमता थी कि वो राजस्व बढ़ा सके और ना ही इच्छा शक्ति थी कि विकास कार्यों पर ईमानदारी से खर्चा कर सके। ये स्थिति थी पिछली सरकारों की और दिल्ली की वर्तमान स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। यही नहीं ये

आंकड़े पूरे तरीके से financial mismanagement का स्पष्ट प्रमाण है, स्पष्ट कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहां यह कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि राजस्व जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए सम्बन्धित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। इसलिए दिल्ली पिछडती गई। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबन्धन एवं अक्षमता के दिन आपदा सरकार के दिन चले गए। हमारे एक लाख करोड रूपये के ऐतिहासिक बजट में किये जाने वाले capital expenditure अध्यक्ष महोदय, उनको दुगुनी बढ़ोतरी दी गई है, दुगुनी डबल कर दिये गए हैं। जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15089.25 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28 हजार करोड़ रूपये का capital expenditure दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में capital expenditure की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए डवल्पमेंट में कम खर्च किए। हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास संसाधन नहीं है। विडम्बना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केन्द्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका न होता तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी तथा सीवर आदि के विकास कार्यो में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं

होती। राजनैतिक कारणों से हर योजना को रोका गया। परन्तु दिल्ली का दुर्भाग्य रहा। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं। सारा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन पर आधारित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की गई, पूरे देश में लागू की गई। लाखों जरूरतमंद नागरिकों को इसका सीधा फायदा प्राप्त हुआ सीधा फायदा, परन्तु केन्द्र सरकार के निरंतर अनुरोध करने के बावजूद लगातार कहा गया कि इसे दिल्ली में लागू कीजिए, लागू कीजिए परन्तु दिल्ली में वो लागू नहीं की गई। सिर्फ इसलिए कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो चाहते थे कि इस योजना में उनका नाम जोड़ दिया जाए। तब वो लागू करना चाहते थे। उनका नाम जोड दिया जाए और इसजिद का खामियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ा। कितनी तकलीफ की बात है जिन स्वास्थ्य सेवाओं का नाम केवल नाम के कारण उन्होंने दिल्ली को आयुष्मान भारत से तोड़कर रखा। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूं कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया शपथ के तुरन्त बाद पहली कैबिनेट की मिटिंग करके 'आयुष्मान भारत' को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने किया

अध्यक्ष महोदय और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केन्द्र के द्वारा दिए जा रहे पांच लाख रूपए के इन्श्योरेंस के साथ-साथ दिल्ली सरकार उसमें टोपअप करके और पांच लाख रूपए का अतिरिक्त इन्श्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब दस लाख रूपये का इन्श्योरेंस मिल पायेगा और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रूपए आबंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे और महिलाओं का सशक्तिकरण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है, हमेशा से पहला स्थान रखता है। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जब 2014 में सरकार बनी तो लालकिले की दीवार पर वहां खड़े हो करके जो लोगों के ध्यान में भी नहीं थी समस्या, पूरा का पूरा देश जिस ओपन डेफिकेशन से गुजर रहा था, प्रधान मंत्री जी ने महिला शौचालयों की बात करी और पूरे देश में शौचालय बनाये गए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को ''महिला समृद्धि योजना'' के तौर पर लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हैड में हमने 5100 करोड़ रूपए का प्रस्तावित प्रावधान किया और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अन्तर्गत जिसमें 21 हजार रूपये गर्भवती महिलाओं को और छः पोषण किट

दी जायेगी उसमें 210 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत, हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होंगी। ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'' ये भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्लीवासियों की सुख-सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थायें करेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से, पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता, संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित वर्ष में आय तथा राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटाकरके 69500 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रूपए का आबंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रूपये का आबंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटाकरके 36,650 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ रूपए के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रूपये किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रूपये की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता

होगी। इसलिए पूरक अनुदान मांगों के अनुमोदन हेतु सदन से मैं अनुरोध करती हूं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का बजट का अनुमान प्रस्तुत करती हूं। मुझे फिर से यह घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर एक लाख करोड़ रूपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही सम्भव हो पाई है ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित एक लाख करोड़ रूपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रूपए के tax revenue से, आप ये मत सोचिए ये पूरा tax revenue एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जेनेरेट करेंगे tax revenue से 750 करोड़ रूपए के non-tax revenue, 15,000 करोड़ रूपए लघु ऋण से, 1000 करोड़ रूपए केन्द्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रूपए केन्द्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रूपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि Opening Balance से पूरा किया जाएगा और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72 प्रतिशत जो है वो राजस्व व्यय है कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 28 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने दस मुख्य बिंदुओं को फोकस एरिया जिसे हम कहें 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि हम सब जानते

हैं कि पूरी तरिके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो पहला हैड जिसमें बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली और सड़क का विकास इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इन्फ्रास्ट्रक्चर पे केवल बाते नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जायेगी जिसमें स्मार्ट इन्फ्रा स्मूद रोड्स और सीमलैस कनैक्टीविटी अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी। बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक समय दिल्ली के मालिक ने दिल्ली को लन्दन बनाने का सपना दिल्लीवासियों को बेचा था।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः बीच-बीच में आकर के कुछ-कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आये फिर कुछ-कुछ बोलकर के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, incomplete projects ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाये। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था उतना होर्डिंगों में खर्च होता था। उससे ज्यादा मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में

कुछ नहीं था पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था। अखबारों में पूरी ऐड थी। देशभर में थी ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप्प कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टी से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक सुरक्षित और हाइटैक इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेस वे, सीमलैस कनैक्टिविटी, ऐलिवेटिड कोरिडोर्स और स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है जो दिल्ली को ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है, ये बजट वो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं we must invest in infrastructure today for better tomorrow. आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं। वो कहते हैं कि better infrastructure is about connecting dreams and accelerating progress. यानि बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना। प्रधानमंत्री जी के दिखाये हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजैक्ट को लॉच करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनैक्टिविटी में सुधार के लिए एक हजार करोड़ रूपया आवंटित करने का प्रस्ताव है और

सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3843 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है 3843 करोड़ रूपए की। योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था पड़ा रहता था वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे। उनके भी प्रोजैक्ट फाइलें लटकी रहती थी, आप चिंता मत करिये सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा। सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रूपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का। एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी-झोपड़ी और

जे.जे. कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था, परन्तु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधायें भी मुहैया नहीं करवाई गईं कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए तभी रीयल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है और इसलिए झुग्गी-झोपड़ी और जे.जे. कॉलोनियों में बुनियादी सुविधायें मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है हम झुग्गी-झोपड़ियों और जे.जे. कॉलोनियों के विकास के लिए डूसिब को 696 करोड़ रूपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रूपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहां बहन-बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं हैं। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झुले नहीं हैं आज भी वहां नालियां खड़ंजे बुरी तरिके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहां जाते हैं उनको डराते हैं भाजपा आयेगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रूपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहां पे जो कि आप की तुलना में 157 प्रतिशत अधिक है। ये जहां पे फुटपाथ बनेगा जहां पे नाली खड़ंजा बनेगा। जहां शौचालय बनेंगे स्नान घर बनेंगे। शीशु बाटिकायें बनेंगीं इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी

वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। पिछली बार अध्यक्ष जी पिछली बार पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ लेने नहीं दिया। क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी तो दिल्लीवालों को उसके निमित्त किसी को लाभ नहीं लेने दिया। अब हमारी जो ये सरकार है इस योजना को हम स्वीकार करेंगे, ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके और इस योजना के तहत हमने 20 करोड़ रूपए का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसी तरीके से हमने विधायक निधी में 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया। इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत नहीं छोड़ी पर हमने प्रावधान पूरा किया है। किसी विधायक को बजट की कमी ना हो, कागजों पे नहीं पूरा मिलेगा। आपका तो केवल कागजों पे रहा पूरा विधायकों को विधायक निधी पूरी दी जायेगी ऐसा मैं आपके माध्यम से अपने पूरे विधायकों को विश्वास दिलाती हूँ। भोजन कागजों पे था जनाब कागजों पे था किसी को ना मिला। अरे दिल तुम्हारे दिल का दर्द बाहर निकल के आ रहा है संजीव भाई। ऐसा हमें पता है और रिपोर्ट है मेरे पास पूरी कि आपके विधायकों में क्या खर्च हुआ। हमारे वाले तो फिर लड़-झगड़के काम करवा गए। कोई नहीं, कोई नहीं और भोजन हर इन्सान की बुनियादी जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिती में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी जिनका ये जो जन्म शताब्दी वर्ष है दिल्ली में 100 जगहों पे, 100 जगहों पे अटल कैंटीन के नाम से पोष्टिक, 100 जगहों पे जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली

जायेगी और उस मद में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ रूपए का। यह बजट केवल सड़कों, पुलों, फ्लाइओवर के निर्माण का दस्तावेज नहीं है अध्यक्ष जी। बल्कि पूरी दिल्ली के भविष्य को फिर से सुधारने के लिए रोडमेप है, ये पूरा रोडमैप है। अब दिल्ली की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि प्रगति की धमनियां बनेंगी। प्रगति की धमनियां बनेंगी अब दिल्ली की कनैक्टीविटी सिर्फ ट्रैफिक सुधार नहीं आर्थिक विकास का इंजन बनेंगी और अब दिल्ली का इन्फ्रास्ट्रक्चर सिर्फ निर्माण परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि समृद्ध और आत्मनिर्भर राजधानी की पहचान बनेगी। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में बहुत फर्क है, ठीक कह रहे हो आप बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभातें हैं। आप केवल वायदे करते थे हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे हम मिलके काम करने के लिए आते हैं। आपकी पढ़ी-लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड़यंत्रकारी योजनायें बनाने में लगाती थी, षड़यंत्रकारी योजनायें पढ़ी-लिखी सरकार और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीशमहल बनवाया हम गरीबों के घर बनवायेंगे। आपने, आपने अपने लिए लाखों रूपए के पॉट बनवाये, पॉट टॉयलेट पॉट हम झुग्गीवालों के लिए शौचालय बनवायेंगे। हम झुग्गीवालों के लिए शौचालय बनवायेंगे, स्नान घर बनवायेंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इक्कठा किया हुआ राजस्व टैक्स का पैसा पूरे देश

की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया। दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया पहला मुख्यमंत्री है भई पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद कूद के यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम हम उसी पैसे को एमएलए भी नहीं रहा कोई बात नहीं दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता ने जो तय किया। हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़के बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया सारी दुनिया जानती है, सबको पता है, परन्तु हम अधिकारियों के साथ सामन्जसय स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप में और हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो। आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी। कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है आप केवल बातें बनाते थे हम विकसित दिल्ली बनायेंगे। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर भी आयेगा, कभी तुम्हारा दौर आया था अब हमारा दौर आयेगा। दूसरा सेक्टर जो मैं सोचती हूँ वो इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस का है। उद्योग और निवेश जोकि समृद्धि का रास्ता है अध्यक्ष जी। प्रगति का आधार है और जहां उद्योग फूलते-फलते हैं अध्यक्ष जी वही समाज आगे बढ़ता है। जहां निवेश आता है तो ना केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि रोजगार के नए द्वार

भी खुलते हैं। अध्यक्ष जी दिल्ली जो कभी व्यापार संस्कृति, उद्योगिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी, बीते वर्षों में अव्यवस्था लाल फीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास की दौड़ में दिल्ली पिछड़ती जा रही है। कितनी बुरी स्थिति है कि एक अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि कोई भी छोटे से छोटा अफसर बड़े से बड़े व्यापारी को जाके धमका देता है। उसको टॉर्चर करता है ऐसी दिल्ली में व्यापारी वर्ग कितना परेशान होगा आप समझिये जिसके कारण से बड़े-बड़े उद्योग ठप्प पड़े हैं। व्यापारियों के लिए एक नई नीतियों का इंतजार है। निवेशकों का दिल्ली पर से भरोसा टूटता गया और अब दिल्ली को व्यापार और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल केन्द्र बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लिया है कि हम ये काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है ईज ऑफ डूईंग बिजनस और मेक इन इंडिया इसकी तर्ज पर हम दिल्ली में नवाचार, उद्यमी अनुकूल और निवेश प्रेरित औद्योगिक क्रांति की नींव रख रहे हैं अध्यक्ष जी ये एक दिल्ली का नया अध्याय यहां से शुरु होने वाला है। ये बजट केवल नीतियों की घोषणा नहीं है बल्कि व्यवसायियों को निवेशकों और स्टार्टअप से वास्तविक राहत देने का ठोस रोडमैप होगा ठोस रोडमैप होगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोजगार दे सकते हैं। गरीबी कम कर सकते

हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं बाबा साहब ने कहा था। हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी अध्यक्ष जी नई औद्योगिक नीति जो की अभी तक नहीं है इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा, दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी साथ ही एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो दिल्ली को सुरक्षित, संरक्षित और तेज वेयर हाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउस पॉलिसी हमारी ये सरकार लेकर आएगी। उद्योग विभाग, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेगूलराइजेशन का प्लान भी लेकर आएगा साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूईंग बिजनस को गति मिले। अध्यक्ष जी शहरी कार्य मंत्रालय डीडीए के साथ परामर्श करते हुए लीज्ड इंडस्ट्रियल प्रापर्टीज जो हैं उनको फ्रीहोल्ड भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है बहुत। हमने जब इस बजट के लिये सुझाव लिये तो हमने अलग अलग क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से व्यापारी भाईयों को उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था।एक एक व्यक्ति रो रहा था कि इतने सालों में कभी उद्योग के उस अप्रूव्ड सेक्टर में न सड़क न नाला, न कोई और व्यवस्था, इतनी बुरी हालत में लोग व्यापार करने के लिये मजबूर हैं इसलिये दुनिया एनसीआर की तरफ दौड़ रही है, अन्य राज्यों की तरफ जा रही है कि अपना व्यापार कर सकें। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि इन

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य स्थितियों के सुधार के लिए डवलपमेंट और रिडवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिये एक प्रोग्राम बनाया जायेगा और उस प्रोग्राम के माध्यम से यहां की सड़कें, गलियां, नालियां, खड़ंजा ये सारी की सारी चीजों को ठीक करा जायेगा ताकि वो व्यापारी भाई अपना व्यापार वहां पे ठीक से कर सकें आज मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूं। दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारी गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके लिये आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जायेगी जोकि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। मुर्गीपालन मधुमक्खी पालन, small scale handicraft and handloom activities, small scale food processing आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना ष्टुरू की जाएगी। यह योजना दिल्ली को Delhi Khadi and Village Industries Board के द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य करते हैं जो स्थानीय संसाधनों और कौषल का उपयोग करते हैं, हस्तनिर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान इस योजना में हमने 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर हैं, विषेश रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रानिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक

नई Global Investment Summit जोकि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में Global Investment Summit का आयोजन किया जायेगा अध्यक्ष जी। जो कि हर 2 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दो साल में उसको किया जाए।

अब भ्रश्टाचार और लालफीताशाही से नहीं, पारदर्शिता से और सरलता से उद्योग चलाये जायेंगे। हमारा लक्ष्य है कि फाइलों में योजनाएँ नहीं अटकेंगी, बल्कि जमीन पर उद्योग फलेंगे-फूलेंगे अध्यक्ष जी। ये उद्योग सेक्टर हमारे लिये बहुत बड़ी बात है इसलिये मैं आज इस सदन में यह बात कहना चाहती हूं कि मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाउंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूं, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी।

अगला मद अध्यक्ष जी दिल्ली में जिनसे भी बात करो अब दिल्ली ने न बड़ी बड़ी उम्मीदें करनी छोड़ दी, छोटी छोटी आशाओं पे आ गये। अब वो नहीं कहते बड़ा ये कर दो, ये कर दो, नहीं। हमारी गली में सीवर पानी अब सारी दिल्ली बेचारी छोटी सी आशा पे आ गयी। बहुत बड़ा तकलीफ का मुद्दा है दिल्ली के लिये सीवर और पानी।

Access to Water and Sanitation, and Yamuna Cleaning-

ये हमारा अगला फोकस एरिया है। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान, बनेगा दिल्ली की पहचान।

अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, यह हमारी इस पूरी सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन की गारंटी है निर्मल नदियाँ संस्कृतियों की पहचान हैं।

1. दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को Clean Water और Sanitation उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हैड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9 हजार करोड़ रुपये का। जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की तीन करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। आज दिल्ली की दैनिक मांग जो है 1,290 MGD पानी की है परंतु मिल हमें 1,000 MGD पानी पाता है 900 कुछ परंतु इस पूरे अंतर को पाटना जरूरी है।

दिल्ली में आज की डेट में मैं कहूं तो हम तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे धरातल पे चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में तो पूरी दिल्ली एक ही चीज देखती है टैंकर घोटाला। घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिये वाटर टैंकर्स में जीपीस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है जो कि एंडरायड मोबाइल एप से जुड़ा होगा, उसपे लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे और नागरिक वहां के लोकल रेजिडेंट आरडब्ल्यूए अपने टेंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है, तो सब में जीपीएस होगा और एक उसका कमांड

सेंटर यहां पे होगा जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाये। हमने 10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली बस्ती चली गयी कभी एक प्लांड वे में नहीं बसी। आज यहां पाईप लाईन डाल दी, कल को उखाड़ दी, कल को कहीं और जड़ दी। पहले सड़क बन रही है फिर पाईप लाईन डल रही है। ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली में कहां 9 मी. डायमीटर की सीवर लाईन चाहिये कि उससे बड़ी चाहिये लोग परेशान हैं न ऐसी केई प्लानिंग हुई कि सौ साल के विजन के साथ में दिल्ली को डवलप किया जाता। आज जितनी भी सीवर लाईन है जितनी भी पानी की लाइनें हैं वो दिल्ली में जर्जर अवस्था में हैं। लोग उस पानी की लाईन क्योंकि जर्जर है तो उसमें सीवर का मिक्स पानी इस्तेमाल करने के लिये मजबूर हैं ऐसा पानी आप ये समझिये नहाना धोना तो छोड़ो घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। और सीवर बैक होना और ओवर फ्लो होना तो दिल्ली का फीचर बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये सारी परियोजनाएं रेंडमली न चलें, प्लांड वे में हो इसके लिये हमने जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिये परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का हैड किया है जो दिल्ली आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम से जुडी हुई सारी व्यवस्थाओं को खड़ी करने में अपनी एक्सपर्ट राय देगा उसके लिये 10 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से क्योंकि पूरी दिल्ली का जो सिस्टम है उसमें इतना लीकेज है आप हजार एमजीडी पानी जो आपको मिल भी रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ

तो उसमें जो नहर है, कच्ची नहरें है वो पानी जमीन में चला जाता है वापिस उसमें 30 परसेंट लीकेज धरती में चला जाता है तो कितना बचा। फिर उसके बाद में कोई पानी चोरी हो जाता है टैंकर गायब हो जाते हैं। जितना पानी शुरू से चलता है वो आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाता है यूजीआर तक। इन सारे सिस्टम को चेक करने के लिये हमने 'स्काडा' सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजीशन सिस्टम को हायर करेंगे और इंटेलीजेंट मॉनिटरिंग लगायेंगे मीटरिंग करेंगे और इसके लिये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है दिल्ली में अब पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी डेढ सौ करोड़ इस हैड में रहेंगे इंटेलीजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। केवल बातें होती रही दिल्ली में, काम करने का प्रयास ही नहीं किया। दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते थे हमारे यहां की लाईनें, हमारे यहां का सीवर, हमारे यहां की बुरी हालत है। सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उसमें खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती। वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे अध्यक्ष जी कैसे यमुना साफ होगी, इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिये बर्बाद कर दिये। बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला, बर्बाद कर दिया। कसमें खाई यमुना साफ करूंगा परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपये की

लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिये रखे हैं 500 करोड़ रुपये। ढाई सौ करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिये रखे हैं 250 करोड़ रूपये हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिये रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिये सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही आर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल दो हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहां बैठे हैं हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहां बैठे हैं 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराये पे लाने के लिए आर्डर दे दिया गया था और भी जितनी जरूरत है मंगाई जायेगी। 20 करोड़ रूपये हमने इस हैड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाईन के रेनोवेशन के लिये 10 करोड़ रूपये का हैड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल को रोकने के लिये उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी उसमें ढाई सौ करोड़ रूपये का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ ड्रेन में जो परिवर्तन करने है उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हैड में ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिये पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद जब ये सारे काम आप लोग इंप्लीमेंट करा

लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिये और एफिशियंसी बढ़ाने के लिये 200 करोड़ की राशि से जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है जिसका 30-35 प्रतिशत पानी लॉस हो जाता है उस ओपन कनाल को पाईपलाईन में कनवर्ट किया जायेगा पाईपलाईन के माध्यम से आयेगा ताकि न चोरी हो, न लीकेज हो। ये काम ये 9000 करोड़ के काम बता रही हूं अध्यक्ष जी मैं, जल संकट से निपटने के लिये हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोर वेल और रेनी वेल को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडिज़ के उद्धार के लिए ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक हैं बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडिज़ वाटर बॉडिज़, उन वाटर बॉडिज़ को पुररूद्धार के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि हमने आवंटित की है और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रूपये की राशि रखी गयी है डेढ सौ करोड़ रूपये की। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी ये है, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है। इसमें हमें वो मदद करें और उन सब के लिये हमने इसी लिये इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वादा दिल्ली सरकार के लिये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली,

जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारी सीवेज जब आपके वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का तो यमुना साफ होगी कैसे। केवल झूठे वायदे, झूठी कसमें पिछली सरकारों ने खाई और पिछली सरकरों की उदासीनता ने दिल्ली की न तो प्यास बुझाई, न जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया।

परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामी गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर, हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ कर के बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिये प्रतिबद्ध हैं। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिये, एक नदी नहीं है बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी मां है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है। हम सब के लिए जीवन रेखा है लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेगें इसके लिए हमने 500

करोड़ रूपये की लागत से 40 डिसैंट्रलाइज सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे इसके लिए हमने 500 करोड़ रूपये की अलग से व्यवस्था की है ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए अध्यक्ष जी इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा एसटीपीज़ हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशन कैपिसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सैन्टर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उसपे चल रहे हैं एफिशियंसी पर चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रूपये की लागत से मार्डन मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैण्डर्डस के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने दो हजार करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा तो कैसे होता पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लींन ड्रीकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, कलीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जलसंकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी

समझ में आती है पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूं इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी।

मैं चौथे मद पे आती हूं जो कि हैल्थ और एजुकेशन फोर ओल शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो-शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक हजार की आबादी पे अस्पतालों में पांच बेड उपलब्ध होने चाहिए एक हजार की आबादी पे कि पांच तो हों कम से कम पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल दो ढाई बेड की एवरेज मिलती है ये दिल्ली का स्वास्थ्य

मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहां पर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी दवा के काउंटर, मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं, घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए किसी ओपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल, डाक्टर, नर्सिंग, पैरामैडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे है। एक एक एमडी के पास में एक एक एमएस के पास में चार चार पांच पांच अस्पताल हैं। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है, इन्होंने 5-5 अस्पताल एक-एक आदमी को दे रखे हैं, वो खुद आकर बोलकर गये, खुद आकर के सारे एमएस बोल गये कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाये, 5-5 छोड़े हुए हैं, तनख्वाह तो वही है कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है और इन्होंने नहीं, ताकि ज्यादा लोगों के हाथ में न रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में, साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सीटी-स्कैन, एमआरआई बाकि जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं सबका अभाव है। मैं जी.टी.बी. अस्पताल में गई, वहां के डॉक्टरों ने कहा कि मैडम यहां जो एमआरआई की मशीन है वो 15 साल पुरानी है जबकि 10 साल में मशीन एक्सपायर हो जाती हैं, बताइये उस मशीन पर बड़े-बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी-छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार देकर के गये हैं।

और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया है। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किये, करोड़ो करोड़ रुपये खर्च कर दिये और आज भी ऐसी स्थिति में है न सिर, न पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होके कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए, दो अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए, ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। सात प्रोजेक्ट ऐसे हैं, सात प्रोजेक्ट ऐसे हैं जोकि आनन फानन में बना दिये गये, 2 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है जीरो क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोर्टा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है, आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते, आज तो उसको बनाना तो दूर उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को सौ-सौ करोड़ रुपये की पेनल्टी सरकार से दी है ठेकेदारों को, सौ-सौ करोड़ रुपये की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य कि पूरी की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेकर आयें, उसका काम करवाये और उसके लिए हमने बड़ा हैड क्रिएट किया है एक हजार करोड़ रुपये का, एक हजार करोड़ रुपये का।

हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरूष सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पायेंगे इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किये हैं और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पोलिसी इसका लेकर आना है उन सारी पॉलिसिस को लेकर जायेगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागजों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयां दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी, कागजों पर ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किये जाएंगे अध्यक्ष जी।

मैं बात कर रही थी 'आयुष्मान योजना' की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्तावित व्यय है।

साथ ही पीएम-भीम योजना के लिए जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा उसमें 1 हजार 666 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा हमारी सरकार PM-JAY के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपये का आवंटन हमने तय किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगूलरेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसायटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं।

बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3421 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है जो की पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं तो 6874 करोड़ रुपये की योजना और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6874 करोड़ रुपये का।

अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पर दिल्ली को गुमराह किया गया, शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्यों को

वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे जो बच्चा नौवीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा ग्यारहवीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे उसको ओपन स्कूल भेज देते थे और रिपोर्टों के अनुसार हर साल नौवीं और ग्यारहवीं में डेढ़ लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है हर साल। कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिये आप, दूर भागिये। हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाएं ताकी हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पर भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है 'यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए।' और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नजदीक मिले।

सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नये 'सीएम श्री स्कूल' खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल नेशनल

एजुकेशन पोलिसी से जुड़े होंगे जिसका पूर्ण अनुपालना वहां की जायेगी इसमें national curriculum frame work for school education 2023 भी लागू किया जायेगा। ये स्कूल 'पीएम श्री स्कूलों' की तर्ज पर खोले जायेंगे, इस योजना के लिये हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रूपये का।

साथ ही मैं बता रही थी कि हमारी सरकार ने, पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरूआत करने जा रही है सरकार, जिसके अन्तर्गत हम JEE, NEET CLAT, CA इस तरह की जितनी परीक्षायें हैं इन सबकी तैयारी के लिये छात्रों को प्राफेशनल मार्गदर्शन देंगे और सभी को देंगे। वो योजना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के नाम से शुरू की जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद-4 के अनुरूप बनाया गया है इस योजना को, इस योजना में हमने 21 करोड़ रूपये की बजट राशि रखी है 21 करोड़ रूपये की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत 'राष्ट्रनीति' नाम से कार्यक्रम शुरू किया जायेगा जिसके लिये हमने डेढ़ करोड़ रूपये का प्रोविजन रखा है जिसका ध्येय होगा कि स्टुडेंट्स को हम शासन, लोकतंत्र, सक्रीय नागरिकता, नीति निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दें ताकि वहां से वो जो युवा निकले वो देश का ऐसा नागरिक बनकर निकले जो देश के विकास में अपने आपको जोड़ सके। इसमें युवा संसद, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजीटल शासन, भारत के ग्रामीण और

दूरदराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा अध्यक्ष जी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनकर निकले, इस योजना के लिये हमने एक जो है डेढ़ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हमने भाषा लैंग्वेज लैब खोलने का एलान कर रहे हैं जिसमें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से प्रयोगशालायें खोली जायेंगी जहां आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी सारी भाषाओं को सिखाया जायेगा और उसमें 21 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है 21 करोड़ रूपये।

अध्यक्ष जी, जीवन जीना भी एक कला है और इस कला को बचपन से ही अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा, इस विषय का महत्व समझते हुये हमने 'साइंस ऑफ लिविंग' कार्यक्रम शुरू किया है और उस 'साइंस ऑफ लिविंग' में बच्चों को मैडिटेशन, योगा, इस प्रकार की अन्य–अन्य एक्टिविटियों से जोड़ा जायेगा और इस मद में हमने डेढ़ करोड़ रूपये का बजट रखा है।

अध्यक्ष जी शिक्षा का ढोल पिटने वाली पिछली सरकारें जब मैंने उनका मौका ए मुआयना किया, रिपोर्टें मंगवाई, वर्षों पुराने कम्प्यूटर कुछ–कुछ स्कूलों में पढ़ें हैं जो आज आउटडेट हो चुके हैं, बात कहते हैं कम्प्यूटर की। किसी स्कूल में एक वो खोल दी आपने स्मार्ट क्लास बना दी, एक बोर्ड लगा दिया, आपने उसको कह दिया स्कूल ही स्मार्ट स्कूल हो गया परन्तु हालत इसके

विपरीत है। हमने उन चीज़ों की कमी को दूर करने के लिये सीबीएसई के मापदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 नई कम्प्यूटर लैब बनाने के लिये 50 करोड़ रूपये का फंड आवंटन किया है, 50 करोड़ रूपये का फंड नई कम्प्यूटर लैब बनाने के लिए।

इसके अलावा स्मार्ट क्लासिस बनाने के लिए अध्यक्ष जी, स्मार्ट क्लासिस बनाने के लिए 100 करोड़ रूपये का फंड रखा गया है। हमारा टारगेट है कि चरणबद्ध तरीके से 7 हजार क्लासिस को कम से कम हम कम्प्यूटराइज करें, इसमें स्मार्ट क्लासिस उसमें दें और ये एक लेवल ऐसा आए कि हर क्लास में स्मार्ट क्लास कह सके हम।

अध्यक्ष जी, शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने की बात अपने संकल्प-पत्र में भी कही थी। और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो दसवीं पास करके ग्याहरवीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे और उस मद में हमने साढ़े सात करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहां से करती हूं।

एक और नया प्रोजेक्ट NEEEV (New Era of Entrepreneurial Ecosystem and Vision) ये कार्यक्रम शुरू किया जएगा। इस NEEEV में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20

करोड़ रूपये का NEEEV के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है, 20 करोड़ रूपये का।

तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड के प्रोजेक्ट के साथ Delhi Skill and Entrepreneurship University के लिए 230 करोड़ रूपये, Netaji Subhash Technical University के लिए 57 करोड़ रूपये, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University के लिए 37 करोड़ रूपये, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women के लिए 21 करोड़ रूपये, Delhi Technical University के लिए 42 करोड़ रूपये और Industrial Training Institutes के लिए 68 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये गये हैं।

सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी इसके लिए जो डीडीए ने भूमि आवंटित की थी, 160 एकड़ की जमीन जिसमें कि पूरा का पूरा वो हैब बनेगा जिसमें DSEU, DPRSU, GGSIPU AND DTU इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में, टेक्निकल यूनिवर्सिटिज और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रूपये का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पर है उसके लिए भी हमने फंड रखा है।

आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास, आईटीआई शाहदरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और

अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों के माध्यम से संचालित किये जाएं। इससे उनकी बाजार/उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे।

युवाओं में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए हमनें अलग-अलग सेंटर खोलकर के उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है।

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी 'जन-जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार, दिल्लीवासियों के भरोसे पर खरी उतरेगी हमारी सरकार।'

अगला सेक्टर जिसकी बात करूं मैं-टूरिजम, आर्ट, लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम।

'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना है।

अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से दिल्ली में पढ़े-बढ़े, दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनैतिक सफर भी शुरू किया। मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है, यहां पर ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहां का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्जा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है-

''कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है,
कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है,
तो जवाब में यूं कह गई-
कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है।''

ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परम्पराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लालकिले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक हर कोना एक अनुठी कहानी कहता है, हर कौना एक अनुठी कहानी कहता है। हमारी सरकार का संकल्प है, भई अभी तक तो क्या था दिल्ली, लड़ाई-झगड़े, गाली-गलोच, तू-तू, मैं-मैं से ही जानी जाती थी और नहीं तो यहां के नेता वहां भाग-भाग के एड देते

थे, वो बात है दिल्ली से आए हैं भई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। दिल्ली को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल, 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूं, 117 करोड़ का। जहां पर एक ओर सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा जिसका एमओयू हमने पीछे साइन किया और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रैंडिंग की जायेगी, दिल्ली देश की राजधानी उसकी ब्रैंडिंग करके पोजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े इसके लिये हमने 25 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनलस को तैयार किया जायेगा, फैलोशिप प्रोग्राम आयोजित किये जाएंगे, इसके लिए हमने उनके लिये 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ। पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े, देखो टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूं कि शिक्षा का टूरिज्म, हैल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिये और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली

बार ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिये यहां पर रखा है। हम दिल्ली में वार मैमोरियल, कर्तव्यपथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान ऐसी अनेक, यशोभूमि, भारतमंडपम इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी है उन सबको भी इस पर्यटन सर्कट में विकसित करके शामिल करना है। देखें तो सही देश की दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्री: शीशमहल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीशमहल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को। शीशमहल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंटहंट स्कीम शुरूआत, आपने सही पहचाना वो उदास थे,

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्री: शीशमहल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंटहंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना ऐसे नई टैलेंटहंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला प्रदर्शन ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वंय सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस

हैड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है। मैं ये भी बताना चाहती हूं अभी बिहार दिवस गया है। बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं, मैं बताना चाहती हूं कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट साढ़े तीन करोड़ होता था उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया, डबल बजट कर दिया है सर, डबल बजट और इस बजट में कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को की तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, की तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर।

अगला हैड यदि मैं बात करूं एक्सपैंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड डवलपमेंट- गरीब, वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है और ये एक बहुत इंपोर्टेंट सैक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हरएक दुख को दूर करने का प्रण लिया है और मुझे ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है ना स्वर्ग की ना ही पुनर्जन्म की, मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित

लोग हैं दिल्ली के उनके लिए हमने इन्कलूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब-किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है, अंत्योदय। हमारी राजधानी केवल आधूनिक इंफ्रास्ट्राक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक ना बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्यय है और इसी सोच के साथ हमने सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र में हमने, इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ रुपए का बजट रखा है 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 10,047 करोड़ रुपए। इन योजनाओं के माध्यम से हम 9.50 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे जिसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4 लाख़ 18 हजार विधवा एवं संकटग्रस्त बहनें और 1 लाख 30 हजार दिव्यांगजन इसमें शामिल है। वित्तीय सहायता योजनाओं को मजबूत करते हुए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के लिए जो है वो सारी चीजें हम इसको पूरा करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिक के लिए मासिक सहायता ढ़ाई हजार, 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 हजार और एसटी/एससी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 500 मासिक सहायता दी जाएगी

और संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता 2500 हजार से बढ़ाकर 3 हजार प्रतिमाह की जा रही है और इस हैड में सभी योजनाओं के लिए हमने 3,227 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 3,227 करोड़ रुपए का। अध्यक्ष जी बात केवल इतनी नहीं है हम तो सबको सुविधाएं देने के लिए कर ही रहे है। पिछले दिनों मैंने देखा अपने संकल्पपत्र की जितनी चिंता हमें है हमसे ज्यादा चिंता सामने वालों को हो रही है। वो रोज जप रहे हैं हनुमान चालीसा कि जैसे संकल्पपत्र, संकल्पपत्र, संकल्पपत्र और वो कभी बैनर बनाके किसी फुटओवर ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं, कभी बैनर बनाकर के किसी चौक पर खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में 2500 रुपए कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आएंगे, आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे, आएंगे और मुझे ये लगता है..

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः सुनिए, सुनिए, सुनिए। अरे अभी सुन भी लीजिए अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा बोल लीजिएगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि इनको ये मालूम है कि ये देंगे कैसे हमने तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को गढ्ढे में छोड़ा है। मैट्रो की देनदारी, जिस मैट्रो में इन्होंने 6 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है जी। दिये नहीं इन्होंने पैसे। फोटो खिंचवाना, ट्विट करना, हम मैट्रो का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 6 हजार करोड़ रुपए पैंडिंग है मैट्रो के दिये नहीं। डीटीसी में 14 हजार करोड़ रुपए का

नुकसान डीटीसी में। शराब घोटाले में 2 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान, हैल्थ की देनदारियाँ ढ़ाई हजार करोड़ से ऊपर की जो ये इंकम्पलीट प्रोजैक्ट छोड़ गए, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनको लगा की ये देंगे कैसे, पर चिंता मत कीजिए आप हमसे प्रश्न पूछने की बजाए प्रश्न अपने आप से पूछिए अपने गिरेबान से पूछिए की वो वायदे जो आपने 2013-14 से शुरू किए थे, पहला वायदा फ्री वाई-फाई देंगे। आज भी लोग पंजे उठाके देख रहे हैं फ्री वाईफाई कहां से आएगा, कब से आएगा, कैसे आएगा। आज तक नहीं मिला, वो याद कीजिए।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः आज भी नहीं मिला और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा तो माद्दा रखिए और सुनिए..

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः 2018 में चुनाव से ठीक पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिये गये, ले लो ताकि चुनाव जीत जाए। गरीब लोगों को मकान के लिए। आज तक एक को मकान नहीं दिया, वो 52 हजार फलैट जो बनने थे। आज तक एक को, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिये गए, किसी को नहीं दिया, वायदा तेरा वायदा, वादे पर तेरे मारी गई, दिल्ली ये सीधी-सादी, वायदा तेरा वायदा, वायदा तेरा वायदा। वो राशनकार्ड का वायदा, वो पैंशन का वायदा, वो बिजली और पानी। अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, देखिए जरा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप अपनी बारी में बोलिएगा आतिशी जी।

माननीया मुख्यमंत्रीः वो बिजली के बिल, वो पानी के बिल जो लोग लेकर घूम रहे हैं, जिनको कह दिया गया था माफ कर देंगे। सब पैसा खत्म कर देंगे, वो आज भी बिल लेके घूम रहे हैं। वायदा तेरा वायदा, एक वायदे पर तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा-सादा। और जो लोकसभा के टाइम पर, लोकसभा का चुनाव था। एक हजार रुपए देंगे, दिल्ली की जनता से वायदा किया गया। बजट में दिखा दिया 2 हजार करोड़ रुपए रख दिये, दिल्ली की जनता ने सोचा रख दिये होंगे। वो बात अलग है कि उसके बाद भी नहीं जीता। एक भी सीट नहीं आई। पर वायदा, आपने जो-जो वायदे जब-जब किए जरा उस एजेंड़ा को निकालकर देखिये, दिल्ली के साथ आपने कितना बड़ा धोखा किया और दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, कितने शर्म की बात है।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः मैं आपको ये बताना चाहती हूं महिला समृद्धि योजना में, महिला समृद्धि योजना, बहनों को 2500 रुपए देना ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है उसके लिए हमने 5100

करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। और अभी तो सुनते जाइये आपके कारनामें अभी याद आएंगे। दिल्ली में...

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः अरे थोड़ा तो रखिए आतिशी जी।

माननीय अध्यक्षः आतिशी जी आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, आपको मौका मिलेगा।

माननीया मुख्यमंत्रीः हम सुनेंगे आपको।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः वायदे पर तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा-सादा दिल्ली बोल रही है। ये देखिये सुनिये। दिल्ली में सीनियर सिटीजनस की एसोसिएशनस है उनको एक ग्रांट इन एड मिलती थी दिल्ली सरकार की ओर से। पिछले 4 साल से उन सारी सीनियर सीटिजनस की एसोसिएशन को दिल्ली सरकार ने एक रुपया नहीं दिया।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः 4 साल से पेंडिंग है, 4 साल से और हम अपने इस बजट में घोषणा कर रहे हैं कि ये सीनियर सिटिजनस में जो 4 साल से पेंडिंग उनकी ग्रांट है वो भी देंगे, सुनिए। वो भी देंगे, 4 साल से जो पेंडिंग ग्रांट है वो भी देंगे और मात्र डेढ़ सौ, ये जो हमारी सीनियर सिटिजनस की एसोसिएशन है उसको अभी तक ग्रांट मिलती थी और भी अधिक हम डबल कर

देंगे उनको संस्थाओं को पैसे हम देंगे, इस हैड में हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। सबको पुराना 4 साल का पेंडिंग पैसा हमारी सरकार देगी, ये फर्क है आप में और हम में। हम देंगे उनको पैसा इसी तरीके से सरकार ने गर्भवती बहनों के लिए जो 21 हजार रुपए और 6 पोषण किटउस हैड में 210 करोड़ रुपए हम देंगे। अपनी वायदा किया हुआ संकल्पपत्र का वायदा, 210 करोड़ रुपए इस हैड में हमने यहां पर रखा है। पालना, राष्ट्रीय क्रेच योजना, पालना। जब गरीब महिलाएं जाती हैं काम के लिए, पीछे से अपना बच्चा किसके पास छोड़कर जाएं, कहां रखे, कौन उसका ध्यान रखेगा। उसके पास तो कोई मेड नहीं है, वो तो बेचारी खुद मेड है। ऐसे गरीब समुदाय जिनके छोटे-छोटे बच्चे झुग्गी-बस्तियों में वो मजबूर है, घर पर अकेला छोड़ने के लिए इसके लिए हम 500 नया पालना आंगनवाड़ी-कम-क्रेच सैंटर खोलेंगे और उसमें हमने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है ताकि गरीब बहनें निश्चिंत होके काम करने जाए और उनके बच्चे की सम्भाल हो पाए, इस पालना में हम 50 करोड़ रुपए का फंड रख रहे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ियों की जो बुरी हालत है आप सबने अपने-अपने क्षेत्रों में देखी होगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना दो के तहत हमने 206 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिसमें 1000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी की व्यवस्थाएं बाकी चीजें ये सारी वहां क्रिएट की जायेंगी। एक हजार सक्षम आंगनवाड़ी जहां गरीब का

बच्चा आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। एक हजार सक्षम आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए सेफ, सिक्योर और अफोर्डेबल आवास की व्यवस्था करना। अभी इस उद्देश्य से जो वूमन होस्टल की श्रृंखला में सखी निवास योजना चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत कामकाजी महिलाएं, उच्च शिक्षा को प्राप्त छात्राएं उनके लिए सुरक्षित होस्टल और बच्चों के लिए भी डे-केयर की सुविधा दी जाएगी और अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार के 14 कार्यरत महिला होस्टल है और उसमें 1935 महिलाएं उसका लाभ उठा रही है। हम दो नए सखी निवास और बनाएंगे ताकि और बहनों को ये सुविधाएं मिल पाएं। और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जो वन स्टाप सैन्टर केंद्र के द्वारा संचालित योजना है जिसमें कोई पीड़ित महिला एक ही जगह पर उसको सारी सुविधाएं हम देते हैं उन सैंटर्स के रख-रखाव के लिए और उसको बेहतर उसके अपग्रेडेशन के लिए भी हमने 11 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, वन स्टाप सैन्टर और सुरक्षा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है अब पिछली सरकारें तो बात करती नहीं थी उनको तो इलजाम लगाना होता था कोई घटना दुर्घटना हो जाए ये तो काम केन्द्र का है। ये तो है नहीं हमको पुलिस दे दो, हमें ये कर दो। अरे जो था उसको तुमने क्या कर लिया भाई-जो और दे दो, और दे दो ये कहीं इंसान में संतोष होना चाहिए और इसलिए दिल्ली सरकार केन्द्र सरकार के साथ में बैठकर बातचीत करते हुए कैसे दिल्ली में और सुरक्षित माहौल बने और विशेष रूप से बहनों

के लिए उसके लिए जितने दिल्ली में डार्क स्पॉट हैं उन सबको आडेंटिफाईड करके डार्क स्पॉट केवल कैमरा की दृष्टि से नहीं या रोशनी की दृष्टि से नहीं वहां पे एप्रोच पुलिस की कैसी है, वहां रोशनी भी हो, वहां पे आपके जो कनेक्टिविटी भी हो। उन सारी दृष्टि से देखते हुए हमारी दिल्ली में सारे डार्क स्पॉट्स कम कर दिए जाएं। पिंक पीसीआर शुरू की जाए और जो महिला बटालियंस हैं जो महिला पुलिस कर्मी हैं उनको और ज्यादा दिल्ली में लगाया जाए ताकि किसी विपरीत परिस्थिति की राह में कोई भी बहन उनसे मदद ले सके तो दिल्ली में सुरक्षा हो उसके लिए हम महिलाओं की दृष्टि से और ज्यादा सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करेंगे और उसमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग लेंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूं बहुत सारे लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, सड़कों के नीचे किसी पुल के नीचे अपना आश्रय बनाकर के रह रहे हैं उनकी चिंता सरकारों ने केवल सर्दियों के समय करती रही है कि हां भई इनको ले जाइए रैन बसेरों में ले जाओ वो कोई परमानेंट समाधान नहीं है परंतु इन दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए हमने उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करें इसके लिए 5 करोड़ का फंड हमने इस हैड में रखा है। ऐसे ही एससी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए हमने बी.आर. अंबेडकर स्टीपेंड योजना शुरू की है जिसमें कि हम एक हजार बच्चों को ये सहायता देंगे और उसमें 5 करोड़ रूपये का फंड रखा है इस योजना के तहत दिल्ली के आईटीआई

स्किल सैंटर और पोलिटैक्नीक में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को आपको कोचिंग के लिए सहायता दी जाएगी। ये है हमारे एससी समाज के लिए। मैं इसमें एक चीज और संज्ञान में दिलाना चाहती हूं। एक कॉर्पोरेशन है दिल्ली सरकार का डीएसएफडीसी चलता था एक समय में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को लोन देता था, स्किल ट्रेनिंग देता था पर हमारी पिछली पढ़ी लिखी सरकार ऐसी आई कि उस कॉरपोरेशन की हालत अब ये हो गई है कि दूसरों की मदद करना दूर किसी को लोन देना दूर, स्किल की ट्रेनिंग देना दूर उन्होंने अपने कैपिटल फंड को तनख्वाह में खर्चना शुरू कर दिया। बोर्ड की इतनी बुरी हालत है जिस दिन से पिछली सरकार आई उस दिन से उसका डाउनफाल शुरू हो गया। ये आईआरएस जो लोग थे जो पिछली सरकार के पढ़े लिखे लोग थे एक कॉरपोरेशन को भी चला नहीं पाए। आज वो पूरा का पूरा बोर्ड जो है इतनी बुरी हालत में है करने को कुछ काम नहीं है 122 कर्मचारी खाली बैठे हैं बिना किसी काम के तनख्वाह ले रहे हैं उस बोर्ड में करने के लिए कुछ नहीं है। पिछली पढ़ी लिखी सरकार ने जिस बोर्ड को बरबाद कर दिया उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए हमने फंड क्रियेट किया है और उसमें फिर से काम हो उसके लिए हमारा प्रयास है। एक बहुत बड़ा मद है गांव देहात का और वर्षो से उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इस बजट को बनाने से पहले गांव देहात के बहुत सारे भाई हमसे मिलने आए उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताईं।

मैं आज इस बजट के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार दिल्ली के हर गांव और किसान को सशक्त बनाने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित है और इसको पूर्ण करने के लिए फिर से ग्रामीण बोर्ड को बनाया जाएगा और उसमें कुल एक हजार 157 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है जिसमें एक हजार 82 करोड़ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है जो बोर्ड बिल्कुल बंद हो गया था काम नहीं कर रहा था दोबारा से उसको रिवाइव करेंगे और एक हजार 157 करोड़ रूपये ग्रामीण बैल्ट में खर्च किए जाएंगे ऐसा इस सरकार का निर्णय है। साथियो, अध्यक्ष जी, पीएम किसान सम्मान निधि पीएम जी द्वारा चलाई गई योजना है जिसमे अभी छह हजार रूपये की वार्षिक सहायता किसानों को दी जा रही है। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था आज हमें खुशी है उस बात को पूरा करते हुए कि हम टापअप के साथ छह हजार के साथ तीन हजार रूपये और नौ हजार रूपये का अनुदान राशि अपने किसान भाईयों को देंगे और इस हैड में हमने 5 करोड रूपये का प्रावधान किया है। गौशालाएं, दिल्ली की गौशालाएं, मुझे ध्यान है जब नगर निगम का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा एजेंडा बनाया, संकल्प पत्र बनाया हम जिसे संकल्प पत्र बोल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों से कुत्ते हटा देंगे, गाय हटा देंगे, ये कर देंगे, पहाड़ हटा देंगे, सब हटा देंगे। कुछ नहीं हटा पाये, खुद ही हट गये। दिल्ली की जनता ने उन्हें ही हटा दिया, कुछ नहीं हुआ,

कितने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में 4 गौशालायें केवल दिल्ली सरकार अनुदान देती थी परंतु इतने वर्षो से दिल्ली की गौशालाओं को वो अनुदान नहीं दिया गया। कैसे चल रही है वो गौमाताएं, क्या खा रही होंगी, कैसे चल रही होंगी, क्या सुविधा मिल रही होगी, यही पाप तो लग रहा है। यमुना जी ने पाप दिया, फिर गौमाता ने दिया है, वही लग रहा है, बच के रहिये। हमने जितनी भी पेंडिंग ग्रांट थी गौशालाओं की, उनको भुगताने का, उनको देने का निर्णय किया और एक नयी मॉडल गौशाला घुम्मनघेड़ा गांव में उसके लिये 40 करोड़ रूपये का फंड रखा है, मॉडल गौशाला एक आधुनिकता के साथ में जहां पे गौ संरक्षण हो, दूध उत्पादन हो, पशु चिकित्सा हो, सारी सुविधायें वहां दी जायेंगी मॉडल गौशाला उसके लिये हमने 40 करोड़ का फंड रखा है। मुझे मालूम है केवल इतने में काम नहीं बनेगा, और भी काम इस सैक्टर में करना होगा और इसके लिये आने वाले भविष्य में हम समाज का सहयोग ले के नयी गौशालायें खोलें, अगली बार से कुलवंत जी की सीट बदलनी है। ये इनसे बातें करते हैं।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः जो नयी गौशालायें खोली जायेंगी समाज के सहयोग के साथ मिलकर के नयी गौशालायें खोलेंगे ताकि गौमाता को सड़कों पे छोड़ न दिया जाये, सड़कों पे उनकी बुरी हालत न हो, नयी गौशालाओं के साथ दिल्ली की सड़कों से गौमाता को हटा करके उनको यथा स्थान गौशालाओं में पहुंचाने का काम ये सरकार

करेंगी। दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गावों के समग्र विकास के लिए मैंने बताया एक हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया एक हजार करोड़ का। इस राशि का उपयोग सड़क जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा इतना कहना चाहूंगी कि:

"हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे
और जो कहा है वो कर के दिखाएंगे,
हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे
जो कहा है वो कर के दिखाएंगे।"

ये आज आपके सामने ये वायदा हमारा दिल्ली की जनता से है।

अध्यक्ष जी सातवां हेड मैं कहूं जो मुझे समझ में आता है फोक्स एरिया का सार्वजनिक परिहवन का एक नया दौर शुरू हुआ है। दिल्ली दुनिया की तीसरी ऐसी सिटी अभी है जो इलैक्ट्रिक बसिज़ फ्लीट में है जिसमें दो हजार 152 इलैक्ट्रिक बसें हैं इसमें डीटीसी के तहत 1752 इलैक्ट्रिक बसिज़ हैं और डिम्ट्स क्लस्टर योजना के तहत 400 बसिज़ हैं इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 तक इस बेड़े में 5 हजार से अधिक इलैक्ट्रिक बसें शामिल हों इसकी उम्मीद है और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलैक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे इसके लिए हम काम करगें। मैंने बताया कि मैट्रो का जो लोग मैट्रो के नाम पर हमने क्रियेट कर

दिया हमने चौथा फेज, पांचवा, चौथे फेज को देर से चलने में देरी करने में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है उन्होंने उसकी फाइलें आगे नहीं करीं अपना मैट्रो का शेयर नहीं दिया लायबिलिटी नहीं चुकाई इतनी बुरी हालत हो गई कि आज मैट्रो के एकाउंट में हमारे बजट में छह हजार करोड़ की लायबिलिटी पैंडिंग है क्योंकि केन्द्र सरकार ने तो विदेशी कंपनी जायका को दे दी परंतु दिल्ली सरकार ने केन्द्र को दी नहीं ना कभी अपना हिस्सा दिया ना अपनी लायबिलिटी दी केवल केवल उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते थे। वो मैट्रो जो कि 290 स्टेशनों के साथ 394 किलोमीटर मैट्रो नेटवर्क का संचालन कर रही है फोर्थ फेस में तीन प्रायरटी कोरीडोर का 60 प्रतिशत तक काम हो गया है अभी हम पीछे गए थे एक टनल ब्रेक थ्रू सैरेमनी में मैं और सिरसा जी तो तीन प्रॉयरटी कोरीडोर का 60 परसेंट काम जो पूरा हो गया है इसके साथ ही चरण चार के बैलेंस तीन कोरीडोर यानि लाजपत नगर से साकेत जी ब्लाक, इंदरलोक से इंदरप्रस्थ, रिठाला, बवाना, नरेला, नाथूपुर, कोंडली का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली मैट्रो के लिए हमने 2 हजार 929 करोड़ रूपये का आवंटन किया है यानि लगभग तीन हजार करोड़ रूपये का हमने इसमें मैट्रो के लिए बजट रखा है। हम अपना शेयर भी देगें, हम अपना काम भी करेंगे और दिल्ली को मैट्रो की सुविधा के साथ अगले फेसीज के लिए जोड़ेंगे। भारत सरकार के वित्त पोषण से राजधानी में शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू

किया जाएगा। इन केंद्रीय वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए एक हजार करोड़ का आवंटन किया गया है एक हजार करोड़ का और साथ ही दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए वर्ष 25-26 में 12 हजार 952 करोड़ रूपये का फंड हमने ट्रांसपोर्ट के सैक्टर में रखा है 12 हजार 952 करोड़ रूपये का। दिल्ली और दिल्ली में अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए टैक्सी चालक, आटो चालक इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। हम गिग वकर्स के लिए वैलफेयर बोर्ड बनाएंगे। हम सैमी स्किलड वर्कस के लिए वैलफेयर बोर्ड बनाएंगे। मैं अभी देख रही थी अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी बड़े दिनों बाद पब्लिक के सामने आये।

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्री: अरे देख रही थी तो बोलना पड़ेगा न, नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं भई ऐसे न बोलो। और आते ही मुझे लगा कि वो जहां भी थे इतने दिनों से केवल मोबाइल देख रहे थे और मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली, एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली। वो तो राष्ट्रीय मुददा है, एक महिला को। दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी, दिल्ली सरकार ने। अरे भैया हम जितनी योजनायें बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनायें निश्चित दे रहे हैं उसके लिये हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है परंतु एक चीज नहीं होने देंगे जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी वो अब नहीं होगी, अब वो नहीं चलेगा हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सैक्टर में भी महिलायें

उपयोग करती थी सौ, बिलिंग होती थी चार सौ की, हम बनायेंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता न हो वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिये है वो जिस मर्जी बस में जायें, जितनी बार मर्जी जायें, उसके पास एक कार्ड होगा, उस वो कार्ड का इस्तेमाल करेंगी तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकिटिंग के नाम पे करोड़ो करोड़ रूपये 14 हजार करोड का घाटा! पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था न पिंक को मत बदनाम करें। ये कर रहे थे वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाईज किया जायेगा और, और भी सुन लीजिये ये सारी की सारी योजनायें इन सबके उपर काम होगा, सब कुछ देंगे, जो योजनायें पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे और फिर भी सबसे बड़ा बजट दिल्ली का एक लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है। मैं एक बात बताउं, मैं ये सोच रही थी एक वीडियो आयी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने देखी। मंच से बोली, इनके पास एक पूरा सिस्टम है, इन्होंने सैंकड़ों लोग बिठा रखे हैं जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जो सोशल मीडिया वार करते हैं तुरंत कोई इशू उठाओ उसको फिर ऐसा एक्सप्लोर कर दो ये हो गया, ये हो गया एक बड़ा सैक्टर आज से नहीं सालों से चल रहा है। ये लोग दिल्ली को बर्बाद भी ऐसे ही किया और उसको कैसे मुददा बनाना है उसको कैसे मैगनीफाइ करना है उसको कैसे जनता के बीच में प्रस्तुत करना है। एक टिकट वो वीडियो आप ही के पास आई, वो

वीडियो आप ही ने बोली, वो आपको ही बोलने की जरूरत पड़ी, देखिए क्या हो गया? अरे कौन सी महिला का एक भी महिला का टिकट हमने नहीं रोका भई, सबको ऐज इट इज सारी योजना दे रहे हैं और और अच्छे तरीके से देंगे और बेहतर तरीके से देंगे और जो उस योजना के मातहत आता है उन सबको योजना मिलेगी। ये हमारा वायदा है तो आप जितनी मर्जी उन सोशल मीडिया वारियर के साथ में लड़ाई लड़िए पर ये ध्यान रखिए कि ऐसे भी हजारों वारियर्स हैं जो देश हित में इस दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं।

अगला सैक्टर है ऐफिशियेंट इरीगेशन और फलड कंट्रोल सिंचाई में सुधार, बाढ़ का समाधान सुरक्षित होगी राजधानी। ध्यान होगा आप लोगों को दिल्ली में 2023 में जो बाढ़ आई थी इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ थी जो दिल्ली में घटी। कारण, पिछली सरकारों की अनदेखी। करा ही नहीं कभी उस काम को, कभी नालों की डिसल्टींग हुई ही नहीं। कागजों में हो जाती थी, कागजों में डिसल्टींग हो जाती थी बाहर तो 100 ग्राम कूड़ा भी नहीं निकलता था। सौ ग्राम कूड़ा भी कभी नहीं निकला डिसल्ट हुआ ही नहीं परंतु डिसल्टींग हो जाती थी तो दिल्ली में जलभराव क्यों नहीं होगा दिल्ली में बाढ़ क्यूं नहीं आएगी परंतु सुनिए, सुनिए चाणक्य ने कहा है किसी देश की प्रगति के लिए सुन लीजिए चाणक्य जी ने कहा है किसी देश की प्रगति के लिए उस देश के राजा को आने वाली विपदाओं को लेकर पहले से ही सजग होना चाहिए। उन्हें

समय से पहले खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म करना चाहिए और राजस्व में हानि को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो चीज दिख रही है भूकंप आना, बाढ़ आना ये सारी चीजें दिखती हैं। इसके लिये देश की राजधानी दिल्ली तैयार नहीं है, बाढ़ आ जायेगी देश की राजधानी में, ये आपके शासनकाल में ही हो सकता था ये फर्क था। दिल्ली बरसात में राहत की बजाय ऑफत झेलती थी। सड़कों पर जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति, ठहरे हुये पानी में समाई गाड़ियां हैड लाइट, उनकी धंसती सड़कों की तस्वीर हर सीज़न में, हर सीज़न में टीवी पर एक ही देखिये एक बारिश में क्या हाल हो गया, देखिये गाड़ियां घुटने-घुटने हैड लाइट तक डूबी रहती थीं। दिल्ली में water-logging और खराब drainage system एक गंभीर समस्या रही है जिससे हर साल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती रही। दिल्ली की तीन करोड़ की आबादी को हर साल बारिश के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली में बरसात का मौसम ही खराब है लोग चाहते ही नहीं थे बारिश आये लेकिन असल में बरसात खराब नहीं थी अध्यक्ष जी बरसात खराब नहीं थी बल्कि दिल्ली की पिछली जो सरकारें थीं उनका प्रशासन खराब था। उन्होंने कभी भी इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिये कोई काम किया ही नहीं जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पर जल भराव एक आम बात हो गई लेकिन हमारी सरकार इस समस्या को

जड़ से खत्म करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस दिशा में हम लोग Irregation & Flood Control के मद में 603 करोड़ रूपये का बजट रख रहे हैं 603 करोड़ रूपये। वो ड्रैन्स जो कभी जीवन में साफ ही नहीं हुई उनको साफ किया जायेगा उनकी remoulding की जायेगी उनको तैयार किया जायेगा और इन समस्याओं से निपटने के लिये हम बाढ़ नियंत्रण के लिये नालों का पुर्ननिर्माण उसके लिये भी डेढ़ सौ करोड़ रूपये का फंड रख रहे हैं। इन नालों की carrying capacity बढ़ाने के लिये काम किया जायेगा और जितनी बाढ़ नियंत्रण के लिये जो खुले हुये जलाशय हैं ओपन वॉटर बॉडिज़ उनकी सफाई उनकी desilting की भी योजना है और मार्डन मशीनें खरीदी जायेंगी, ये सारी चीज़ें दिल्ली में जल भराव ना हो, दिल्ली में कभी ऐसी आपात स्थिति ना आये और इन सबके लिये काम किया जायेगा अध्यक्ष जी ये विज़न है दिल्ली सरकार का मैं आज आपको बताना चाहती हूं।

अगला जो प्वांइट है हरित दिल्ली स्वच्छ हवा और सतत् विकास Power, Sustainable Development, Green Growth और Pollution Control दिल्ली की जनता वर्षो से परेशान है पोल्यूशन-पोल्यूशन-पोल्युशन काम कभी हुआ ही नहीं grap लगा दो grap लगाना कोई समाधान तो नहीं है। करा क्या, समाधान कैसे होगा कभी सोचा नहीं। दिल्ली सरकार राजधानी के हर एक नागरिक को uninterrupted और affordable बिजली प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है। हम बिजली बजट दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में

आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना और इन सारी बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिये हमने 3 हजार 8 सौ 47 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है 3 हजार 8 सौ 47 करोड़ का अध्यक्ष जी। मेरी सरकार का उद्देश्य है दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रूकावट के 24 घंटे बिजली मिले। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये राजधानी की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये आंतरिक बिजली उत्पादन बहुत जरूरी है। clean renewable ऊर्जा बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार केन्द्र सरकार की Ministry of New and Renewable Energy के साथ MOU करने की प्रक्रिया में है ताकि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके और इस योजना के तहत दिल्ली के आवासिय उपभोक्ताओं को 78 हजार तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी ताकि पब्लिक मोटिवेट हो और वो अपने घरों पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लागू कर सके। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना राज्य का टॉपअप, टॉपअप करने के लिये जितना पहले मिल रहा था उससे ज्यादा देने के लिये दिल्ली ने 50 करोड़ रूपये का बजट तय किया है। एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है overhead wiring दिल्ली जुझ रही है इस overhead wiring से जगह-जगह पर दुर्घटनायें हो जाती हैं आग लगने की और बहुत बुरा लगता है। कई कॉलोनियों में तो ऐसा लगता है कि आसमान भी नहीं देख सकते और हवा, पानी

की भी दिक्कत रहती है overhead बिजली के तार इसको shifting of high tension and low tension transmission line की योजना के लिये pilot project के नाते हम 100 करोड़ रूपये का बजट आबंटित कर रहे हैं। दिल्ली काम करेगी climate change पर दिल्ली काम करेगी air quality पर water resources पर और उनको स्वच्छ और संरक्षित रखना हमारी सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकतायें हैं। दिल्ली को वायु, जल प्रदुषण जैसी गंभीर पर्यावरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हम दिल्ली को वेस्ट मेनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ायेंगे और waste energy के और अधिक प्लांट के साथ में दिल्ली अपनी इन समस्याओं को अपना उससे हट सकेगी उससे निजात पा सकेगी। हम Environemental parameter की मॉनिटरिंग करेंगे, परियोजनाओं को time bound implementation करेंगे और इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के लिये 506 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है 506 करोड़ का बजट अध्यक्ष जी पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया इस फील्ड में। पोल्युशन कंट्रोल और इमरजेंसी मेजर्स के लिये 300 करोड़ रूपये का प्रावधान अलग से किया गया है और साथ ही एक दिल्ली सरकार की स्कीम रही। दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी यानि की RWA और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पार्क को एडॉप्ट किया जाता रहा, तकलीफ की बात है कि संस्थाओं ने पार्क ले लिये पर उनको उनके अगेंस्ट फंड दिया ही नहीं गया पैसा दिया ही नहीं गया लोग तंग हैं परेशान हैं अपनी जेब से कब तक खरचेंगे इसके

कारण से दिल्ली के पार्कों की बदहाली हुई। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी योजना के अन्तर्गत हमने 20 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है जिसमें RWA, NGO Society इन सबको पुराना बकाया भी और नया भी जो है वित्तीय सहायता दी जायेगी। दिल्ली को हरित क्षेत्र में बढ़ाने के लिये वायु प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिये पौधे लगाने का 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही वायु प्रदुषण की real time monitoring और 6 नये CAAQM continuous ambient air quality monitoring अभी जितने हमारे टॉवर्स लगे हैं उसमें और 6 नये टॉवर्स लगाये जायेंगे और दिल्ली ताकि पूरी दिल्ली की पिक्चर आ सके कि एक्चुअल में हमारा AQI कितना है तो इसके लिये हम ये करेंगे। इसके अलावा 32 जगह पर Water Quality Monitoring Station भी लगाये जायेंगे जिससे पानी की क्वॉलिटी को real time monitoring दी जाये ये काम भी किया जायेगा। अध्यक्ष जी दिल्ली का कोई monitoring system ही नहीं है। कोई command system कोई redressal system कुछ नहीं, एप्प बना बनाकर छोड़ दी गई है कोई ये भी नहीं देखता कोई झांककर नहीं देखता कि भई ये एप्प काम कर रही है कि नहीं कर रही है, समस्या आई है तो उसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ। हमने गुड गर्वनेंस के चलते ये तय किया है कि एक Integrated Command and Control Centre स्थापित किया जायेगा जो air quality, water quality, noise level, waste management, traffic jam,

water loggings ये सारी चीजों को पूरी दिल्ली में disaster management हर चीज़ को एक छत के नीचे पूरा का पूरा Integrated Command and Control Centre दिल्ली का बनाया जायेगा जहां grievances भी सुनी जायेगी और उससे संबंधित विभागों को भी देखा जायेगा ऐसा good governance का perform, reform and transform मंत्र के साथ में सुशासन किया जायेगा perform, reform and transform। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सत्ता के माइंडसेट को बदलना होगा, हम सत्ता के माइंडसेट से यहां नहीं आये हम सेवा के माइंडसेट से आये हैं हम गरीब कल्याण को अपना माध्यम मानते हैं और तुष्टिकरण में विश्वास नहीं रखते हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। तुष्टीकरण में विश्वास नहीं है हमारा संतुष्टिकरण में विश्वास है और इसलिये जितने भी हमारे उपायुक्त कार्यालय जिलास्तर पर विभिन्न विभागों के और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभानी है। जिला अधिकारियों से उनकी भूमिका को सशक्त करना है और जिला परियोजना निधि योजना के लिये हम 53 करोड़ रूपये का बजट दे रहे हैं ताकि नीचे डी.एम., एस.डी.एम. लैवल पर ऑफिसिज़ बेहतर हों, वहां के grievances ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके और दिल्ली में एक अच्छा सिस्टम डेव्ल्प हो सके। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिये एकीकृत कमांड जरूरी है जो मैंने कहा Command and Control Centre, Command and Control

Centre के लिये 30 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है बहुत जरूरी चीज़ है दिल्ली में ऐसा होना ताकि किसी भी समय एक ही छत के नीचे हमें समस्या का संज्ञान मिल जाये। पहले की सरकारों की आदत थी कभी स्थानीय निकाय को उसका शेयर देती ही नहीं थी, विशेष रूप से जो पिछले 10 साल में आई। एमसीडी में हम लोग भी रहे, रोते रहते थे पीटते रहते थे भईया दो, कैसे कूड़ा उठेगा, कैसे काम होगा, कैसे नालियां साफ होंगी, कैसे सड़कें रिपेयर होंगी जब आप स्थानीय निकाय को उसका शेयर दोगे ही नहीं। ये मानसिकता थी उनकी सब अपने हाथ में रख लो, सब अपने हाथ में रख लो कुछ नहीं देना, काउंसलरों को फंड नहीं मिलता था इस चक्कर में, कभी मिला नहीं। मतलब नहीं, इनके लिये कोई मतलब नहीं है वो किसी और पार्टी का इनकी सरकार आई तो भी नहीं दिया और जब हम लोग रहे तब तो दिया ही नहीं परंतु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है स्थानीय निकाय के निमित्त जो भी हमारा शेयर बनता है 6 हज़ार 8 सौ 97 करोड़ एक-एक रूपया उन्हें देंगे, एक-एक रूपया उनको देंगे और मैंने तो सरकारी अधिकारियों को दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुये ऑफिसरों को बुलाकर कह दिया है कि और चाहिये और भी ले लो पर दिल्ली में कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिये जो चाहिये वो लेकर जाओ, जो सुविधा चाहिये, कर्मचारियों को तनख्वाह दो, हर एजेंसी की पेमेंट क्लीयर करो परन्तु दिल्ली में कूड़ा नहीं पड़ा होना चाहिये ये हमारी प्राथमिकता है

इसके लिये हम 6 हज़ार 8 सौ 97 करोड़ दिल्ली को उसका अपना शेयर देंगे। दिल्ली में एक बहुत important segment है हमारे कोर्ट, ये कोर्ट सालों से बुरी अवस्थाओं में चल रहे हैं कभी सरकारों ने इस मद पर पैसा खर्च नहीं किया कि कोर्ट बेहतर हो वहां सुनवाई speed up हो, वहां का सिस्टम जो है अपडेटिड हो परन्तु दिल्ली की ये सरकार। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल हैं उसमें से 200 और कोर्ट रूम जोड़कर कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हमारी योजना है और शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी जैसे इन सबके लिये हमने 490 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और hybrid system of courts उसकी सुनवाई के लिये डिज़ीटल सुनवाई के लिये 200 करोड़ रूपये का प्रावधान हमने किया है। इन सारी न्यायिक योजनाओं के लिये टोटल मिलाकर 927 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। हम सबने देखा दिल्ली का Fire fighting System बेजान है, आग लगती है तो आग बुझाने के लिये गाड़ियां गलियों में पहुंच तक भी नहीं पातीं। रोज़ घटनायें, दुर्घटनायें कभी चांदनी चौक की कभी सदर बाजार की कभी किसी अन्य क्षेत्र की हम सुनते हैं। जो फायर स्टेशन है वर्षों से बुरी हालत में पड़े हैं उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं है परन्तु मैं आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है ताकि वो छोटी-छोटी गलियों में जाकर के फायर फाइटिंग कर सकें, आग बुझा सकें, किसी के जान माल की हानि ना हो ये काम

हमारी दिल्ली की सरकार करेगी और इसी तरीके से अपडेटिड मशीनरी खरीदने के लिये बाकी fire towers, ariel ladders, split form सारी मशीनरी खरीदने के लिये पूरे इंतजाम करते हुये दिल्ली फायर सर्विसिज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम 110 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान कर रहे हैं 110 करोड़ रूपये का और ये भी बताना चाहूंगी कि Delhi Fire Station के जो मुख्यालय है क्नॉट प्लेस में जो वर्षों से बुरी हालत में पड़ा है उसको नया बनाया जायेगा अपडेटिड और ऐसा जोकि अंर्तराष्ट्रीय मानकों का फायर स्टेशन होगा ऐसी योजना हमारी दिल्ली सरकार की है। इस तरीके से मैं बताऊँगी कि दिल्ली फायर सर्विसिज के तहत पूंजीगत परियोजनाओं में हमने 125 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। Home Guard volunteer एक बहुत बड़ा विषय है दिल्ली सरकार के लिये, इसकी अधिकष्टत संख्या जो है वो 10 हज़ार 2 सौ 85 से बढ़कर 25 हज़ार करने का प्रस्ताव किया गया है। अलग-अलग दिल्ली के वर्गों के लिये हमने बताया कि व्यापारी बोर्ड बनाया जायेगा गिग वर्कर्स के लिये मैंने बताया, घरेलू सहायकों के लिये, ऑटो-टैक्सी ड्राइवर्स के लिये इन सबको सामाजिक सुरक्षा की योजना के तहत cover मिले ये हमारा प्रयास होगा। कामगारों का शोषण करने वाले व्यक्ति और एजेंसियां जो उनका शोषण करती हैं उस शोषण पर रोक लगे। हमारी सरकार अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के लिये कल्याण बोर्ड को स्थापित करके उसके लिये हमने 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। एक प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे

विभिन्न क्षेत्रों के नये युवा दूरदर्शी लोगों को शामिल करने के लिये Chief Ministers' Young Visionary Innovation Programme शुरू करें जिसमें युवाओं को सरकार के साथ जोड़ा जायेगा और उनके नई ऊर्जा के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और उस हैड में हमने 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। दिल्ली में जेल परिसर भी है, ध्यान ही नहीं दिया कभी सरकारों ने कैसे काम कर रही है वो जेल। अब देंगे, हां अगर अब इनको मौका मिलता तो शायद देते क्योंकि दिक्कत हो रही होगी ना वहां सुविधायें नहीं मिली होंगी..

...व्यवधान...

माननीया मुख्यमंत्रीः पर दिल्ली जेल के तत्वाधान में एक society बनाई जायेगी, दो-तीन तरह से हमने सोचा है एक तो जो अलग-अलग कौशल स्कील्स के माध्यम से जो जेलों में सामान बनता है हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार जहां-जहां जिस विभाग में हमें जरूरत है जैसे वो डैस्क बनाते हैं हमें स्कूलों में डैस्क की जरूरत है हम कोशिश करेंगे उनके बनाया हुआ सारा सामान दिल्ली सरकार में उपयोग हो जाये। हम उनकी स्कील को नया आयाम देंगे। अब ये जेल रेज़िडेन्शियल परिसर में है अब जनकपुरी में ही इतना बड़ा तिहाड़ जेल है वहां के लोकल लोगों को भी समस्या होती है और ऊपर से ये पूरा परिसर इतना पुराना हो गया कि वहां कैदियों की सुरक्षा बहुत डेंजरस जोन में है तो ये पूरा का पूरा जेल परिसर दिल्ली के किसी outskirt में shift करके

वो नया जेल बने इसके लिये हम काम करेंगे तो नई जेल का प्रावधान हम लोगों द्वारा किया गया है। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली के जेल परिसरों में मैंने बताया कि उनके प्रोडेक्ट का इस्तेमाल करने के लिये और इस पूरी योजना जो नया जेल परिसर मैंने बताया नया बनेगा उसके लिये हमने परामर्श सर्वेक्षण कार्य के लिये 10 करोड़ रूपये का अभी प्रावधान किया है और ऐसे ही 20 करोड़ रूपये का प्रावधान जो लामपुर में Detention Centre है उसकी रेनोवेशन के लिये किया गया है। अध्यक्ष जी, अब बजट के निमित्त जितनी योजनायें हो सकती थीं उनको तो हमने एडजस्ट कर लिया पर बजट से बड़ा है हमारा विज़न उस विज़न का उस विषय में जरूर मैं बोलना चाहूंगी। जितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं उलझे पड़े हैं कहीं किसी विभाग में कभी कहीं उनको फ्री होल्ड की दिक्कत आ रही है कहीं उनको वैट की दिक्कत आ रही है कहीं उनको जीएसटी की दिक्कत आ रही है, अलग-अलग जगह पर उलझे पड़े हैं। हम लोग अपनी ही सरकार के माध्यम से विवाद से विश्वास तक की योजना लेकर आएंगे ताकी जितने लंबित मैटर्स हैं उनको समाधान देकर के उन्हें भी सकून मिले और दिल्ली सरकार को भी रेवेन्यू मिले। इसके अलावा जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है पहले काम करती थी रोहिंग्या, बंगलादेशियों को लाने के लिए वो सारी कोशिशें रहती थीं। उनको कैसे सिस्टम में घुसाया जाए, उनको कैसे वोट बैंक उनका क्रिएट हो जाए। हम पूरी दिल्ली में सत्यापन अभियान चलाएंगे कि योजनाओं का लाभ, योजनाओं का

लाभ केवल उसे मिले जो दिल्ली का निवासी है, जो उसका अधिकारी है। हर एक व्यक्ति को, हर ऐरे-गैरे व्यक्ति को दिल्ली के राजस्व का पैसा खर्च करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा नहीं लगाएगी। नई सत्यापन हर चीज सत्यापित होगी चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है, चाहे ईडब्लूएस की कोई भी कैटेगरी है हर योजना का सत्यापन करेंगे। दिल्ली में इनफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ऑडिटोरियम, स्टेडियम एक भी अच्छा ऑडिटोरियम हम कहें की जो जनता के उपयोग के लिए है वो नहीं है। आने वाले समय में जरूर ऐसे नये ऑडिटोरियम और स्टेडियम खुलें इसका हमारा प्रयास रहेगा। राज्य का कोई अतिथि गष्टह ही नहीं है कि कोई विदेशी मेहमान आ जाए कहां उसको ठहराएं। राज्य का अतिथि गृह हो इसको हम अपने एजेंडा में लेंगे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः शीशमहल बना दो।

माननीया मुख्य मंत्रीः अरे क्या-क्या बनाओगे उसको म्यूजियम बनाओगे या। नये मेडिकल कॉलेज खुलें ये हमारा वीजन है और जितने आईएसबीटीज हैं आईएसबीटीज उन आईएसबीटीज को भी बिलकुल नया इनफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके नई टैक्नोलॉजी के साथ मल्टी स्टोरी आईएसबीटी बनाया जाए इसके लिए हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये कोई रेंडम डाक्यूमेंट नहीं है। इसमें हर एक चीज का बैलेंस मिक्सचर है। इसमें इनोवेशन और इनफ्रास्ट्रक्चर की ऊंचाई की उड़ान भी है तो इसमें वंचितों के लिए

विशेष आबंटन और आधुनिक गौशाला जैसी जमीनी हकीकतों के लिए फंड भी रखा गया है। कुल मिलाकर के इस फंड में इस बजट में ऊंचाई भी है और गहराई भी है। आज इस पावन अवसर पर मैं दिल्ली की जनता के लिए इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत कर रही हूं तो यह केवल एक वर्षीय वित्तिय योजना नहीं है ये बल्कि राजधानी के भविष्य का एक खाका है, पूरी राजधानी के भविष्य का खाका है ये। इस बजट को आत्म-निर्भर दिल्ली बनाने के लिए सपनों को साकार करने के लिए संकल्प मान लीजिए और जो की संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके विकसित भारत और विकसित दिल्ली बजट से। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ आब्जेक्टिव तय किये। इस बजट से दिल्ली अब सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि प्रगति की राजधानी बनेगी। अब घोषणाओं की जगह योजनाओं पर अमल होगा और अब दिल्ली वादों की नहीं इरादों की राजधानी बनेगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे लेकर जाएगी और दिल्ली देश की ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर सामने आएगी। अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं इस दिल्ली का इतिहास देखती हूं तो मुझे मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि,

''दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है,

दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है,

जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया,

जो भी गुजरा उसे लूट कर चला गया।''

कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार-बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिरशाह की लूट हो या अहमदशाह अब्दाली की बर्बरता हो हर बार दिल्ली ने अपने घावों को भुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया है। दिल्ली का ये शहर कई बार लूटा कई बार उठा। दिल्ली राष्ट्रीय चेतना और पुनर्निमाण का प्रतीक है। दिल्ली फिर उठ खड़ी हुई है और पुनर्निमाण की राह पर चल पड़ी है। ये केवल इमारतों का शहर नहीं है अध्यक्ष जी ये भारत की आत्मा का प्रतिबिम्ब है ये दिल्ली भारत की आत्मा का प्रतिबिम्ब है। यहां खण्डहर भी इतिहास लिखते हैं, यहां दीवारें भी कहानियां कहती हैं जिन्होंने इसे लूटा वो खुद मिट गये ये दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर खड़ी हुई है। आज फिर दिल्ली उठ खड़ी हुई है अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने भविष्य का पुनर्निमाण की नींव रखने के लिए। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली फिर से लूट, कुप्रबंधन की शिकार हुई। जनता की कमाई को लूटने वाले, झूठे वायदे करने वाले, खोखले दावे करने वाले सत्ता में पहुंचे जिन्होंने तिजोरियां खाली करी, समृद्धि को मिट्टी में मिलाया, संस्कृति की पहचान को मिटाया, विकास

को ठप्प किया, दिल्ली वासियों के हक को लूटा वो दिल्ली फिर से उठ खड़ी हुई है अध्यक्ष जी फिर से उठ खड़ी हुई है। मुझे ध्यान है पिछली बार जब आतिशी जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने 23 बार राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य बोला था 23 बार। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो कहते हैं राम राज्य लाएंगे। क्या रामजी ने ये सब कहा था करने के लिए जो राम राज्य लाए। नई सोच नए संकल्प और ईमानदार नेतृत्व के साथ दिल्ली अब आगे की दिशा में बढ़ेगी। आज का ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। दिल्ली के पुनर्जन्म की आधारशिला है ये, पुनर्जन्म की आधारशिला है। अब हर संसाधन दिल्ली के नागरिकों के हित में लगेगा। हर नीति पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बनाई जाएगी। हमने ठाना है कि दिल्ली सिर्फ एक महानगर नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति और सुशासन की पहचान बनेगी दिल्ली। यह बजट दिल्ली के पुनर्जन्म का शंखनाद है। न अब दिल्ली थमेगी और न रुकेगी ये दौड़ेगी चमकेगी और नया इतिहास लिखकर के दिखाएगी। अध्यक्ष जी, हमने सुना है परिश्रम से ही सफल होते हैं मन में सोचने से नहीं और इसी भावना से हमारी सरकार दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। मेहनत में कोई कमी नहीं रखेगी चाहे कुछ भी हो जाए और अपने वक्तव्य को विराम देते हुए मैं दो लाइनें जो कहना चाहती हूं कि हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी, हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी निभाते हैं अगर हम, निभाते हैं अगर कोई वादा

करके लिया हो हमने सफर अपना किसी तूफान के डर से रुकता नहीं इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए संतुति के साथ माननीय सदन के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री वित वर्ष 2025-26 के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पेश करेंगी।

माननीया मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन अनुदान मांगों पर सदन में बजट पारित करने के दौरान विचार किया जाएगा। I present demand for grant for financial year 2025-26 before the House.

माननीय अध्यक्षः इन अनुदान मांगों पर सदन में बजट पारित करने के दौरान विचार किया जाएगा जब दो दिन अभी इस पर चर्चा होगी तो इन पर विचार किया जाएगा। अब मैं आप सबके समक्ष अनुदानों की पूरक मांगे 2024-25 यानी जो वर्ष अभी ऑनगोइंग है। अब मुख्यमंत्री जो वित्तमंत्री के रूप में वर्ष 2024-2025 के लिए Supplementary Demands पेश करेंगी।

अनुपूरक अनुदान मांगें (2024–25)

Chief Minister/Finance Minister: Hon'ble Speaker Sir, I present Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants for the Financial Year 2024-2025 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन Supplementary Demands पर Demand wise विचार करेगाः–

DEMAND NO. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 01 लाख रुपये और Capital में 01 लाख रुपये,

कुल राशि 02 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 3 पास हुई।

DEMAND NO. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 02 लाख रुपये और Capital में 07 करोड़ 50 लाख 18 हज़ार रुपये, कुल राशि 07 करोड़ 52 लाख 18 हज़ार रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 4 पास हुई।

DEMAND NO. 5 (Home)

जिसमें Capital में 01 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

DEMAND NO. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 06 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

DEMAND NO.7 (Medical & Public Health)

जिसमें Revenue में 11 लाख रुपये तथा Capital में 01 अरब 43 करोड़ 69 लाख 71 हज़ार रूपये हैं, कुल राशि 01 अरब 43 करोड़ 80 लाख 71 हज़ार रूपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

DEMAND NO. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 18 लाख रुपये तथा Capital में 01 लाख रूपये हैं,

कुल राशि 19 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

DEMAND NO. 9 (Industries)

जिसमें Capital में 01 लाख रूपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

DEMAND NO. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 08 लाख रुपये तथा Capital में 05 लाख रूपये,

कुल राशि 13 लाख रुपये है, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

DEMAND NO. 11 (Urban Development & Public Works)

जिसमें Revenue में 01 लाख रुपये तथा Capital में 04 लाख रूपये,

कुल राशि 05 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 47 लाख रुपये तथा Capital में 01 अरब 51 करोड़ 32 लाख 89 हज़ार रुपये, कुल राषि 01 अरब 51 करोड़ 79 लाख 89 हज़ार रुपयों की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

Appropriation (No. 01) Bill, 2025

(Bill No. 01 of 2025)

माननीय अध्यक्षः अब मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री Appropriation (No. 01) Bill, 2025 को House में Introduce करने की permission मांगेंगी।

Chief Minister/Finance Minister: Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No. 01) Bill, 2025 to the House.

माननीय अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी/वित्तमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगी।

Chief Minister/Finance Minister:-

Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation Bill (No. 01), 2025 to the House.

माननीय अध्यक्षः अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule बिल का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रष्न है कि खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

माननीय अध्यक्षः अब मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि Appropriation (No. 01) Bill, 2025 को पास किया जाए।

Chief Minister/Finance Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 01) Bill, 2025[2]

माननीय अध्यक्षः मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री जीका प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

[2] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23382 पर उपलब्ध।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

मेरे विचार से, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Appropriation (No. 01) Bill, 2025 पास हुआ।

अब सदन की कार्यवाही दिनांक 26 मार्च, 2025 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 26 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।